Member that health is a State subject. The CMOs, the doctors, etc. are all under the State and the placement of doctors in every Community Health Centre or the Primary Health Centre is done by the State. *(Interruptions)*

श्री शिव चरण सिंह : उत्तर प्रदेश में केन्द्र का शासन है इसलिए आपको करना चाहिये...**(व्यवधान)**

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Minister, U.P. is under President's Rule. *(Interruptions)*

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: I am just answering that.

SHRI SATISH AGARWAL: Uttar Pradesh is under President's Rule. So, you are answerable.

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: The hon. Member did not...*(Interruptions)* My reply to the question was that basically the funding that we were seeking from the World Bank was only to upgrade the State health system. It has nothing to do with hospitals. It is for upgrading the existing facilities. It is for providing equipment, asistance and sending people for training. So, it is for upgrading the already existing facilties so that these come up to a certain level and the people can get help.

श्री मोहम्मद आज़म खान : सभापति जी, यह सही हो सकता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स में अस्पताल बनाने की सुविधा न हो, बहुत से रूल्स ऐसे हैं जिनमें ये नहीं बना सकते। यह बात बहुत हद तक सही है। लेकिन अभी प्रश्न हुआ कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और पिछले पांच महीनों से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवा देने के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या केन्द्र सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता कि ऐसे प्रदेश में जहां इस वक्त भी राष्ट्रपति शासन है और पिछले चार-पांच महीनों से अस्पतालों के पास दवा देने के लिए कोई धन नहीं है, तो ऐसे प्रदेश का जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके लिए कोई धन की व्यवस्था का इन्तजाम आप करवायेंगे?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: मोहतरम मेम्बर ने जो बात उठाई है, मैं इस चीज को गवर्नर साहब से टेक अप करूंगा और अगर कहीं पर भी कोई कमी है जिसको हम पूरी कर सकते हैं तो मैं उसको जरूर पूरी करूंगा।

MR. CHAIRMAN : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Providing Local Purchase system to CGHS (Homoeo) Beneficiaries

*164. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether shortage of medicines exists in CGHS Homoeopathic Dispensaries/units in Delhi;

(b) if so, whether there is local purchase system in case of non-availability of medicines in dispensary/unit;

(c) if so, the category of CGHS beneficiaries enjoying local purchase system benefit; and

(d) the reasons for not providing local purchase system to all the CGHS beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Medicines are provided at the CGHS Homoeopathic dispensaries form the available stock at each dispensary. By and large no serious shortage of homoeopathic medicines has been encountered. In case of short-supply or non-avaibaility of any specific medicine, the dispensary can resort to local purchase from the open market against individual prescriptions until stocks are replenished.

(c) Local purchase is resorted to whenever the dispensary is unable to meet the requirements of a prescription or in case of sudden non-availability. This measure is used only occassionally as dispensaries have to by and large

provide medicines within the stocks given to them by the Medical Store Depot which is guided by formulary made by the experts.

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के युनियन नेताओं द्वारा की गयी अनियमिततायें

165. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इदौर के नई दिल्ली रीजन और ग्वालियर संभाग की विभिन्न शाखाओं में तैनात यूनियन नेता अनेक अनियमितताओं में लिप्त पाये गये हैं और वे निष्ठावान कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में झूठी शिकायतें कर रहे हैं; यदि हां, तो इस संबंध में पिछले, छः महीनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके अनुचित व्यवहार को रोकने हेतु बैंक प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय कार्यालयों के उच्च अधिकारियों द्वारा इन नेताओं को निरन्तर बचाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उनकी दिल्ली की एक शाखा में कार्यरत एक यूनियन नेता को बैंक द्वारा उसे मंजूर किए गए गृह ऋण के उपयोग में अनियमितता बरतते हुए पाया था। बैंक ने मामले की जांच की है और उसे दोषी पाया है तथा दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने का दण्ड उस पर लगाया है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसे ग्वालियर के अधिकारी संघ के एक पदाधिकारी के विरुद्ध एक शिकायत भी प्राप्त हुई है। इस शिकायत की जांच की गई थी और पायी गई अनियमितताओं के संबंध में अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह मामला बैंक के विचाराधीन है। बैंक को इस आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि यूनियन नेता ईमानदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में झूठी शिकायतें कर रहे हैं।

(ग) बैंक ने इस आरोप को अस्वीकार किया है कि उच्च अधिकारी नेताओं का बचाव कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Advise by IMF regarding curbing unproductive Public expenditure

*166. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether IMF has asked to curb unproductive public expenditure in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action proposed to reduce Government expenditure?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The summing up of Acting Chairman of the IMF Board of Directors at the conclusion of the 1996 Article IV Consultation with India mentions that cutting back on unproductive expenditures would help free resources for such priorities as infrastructure and the social sectors, including health and education.

(c) Keeping the Government expenditure under control is a continuous process and instructions in this regard are issued from time to time.

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सुरक्षा कमियां

*167. **श्री रामजी लाल:**
श्री ओम प्रकाश कोहली:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दो व्यक्ति नई दिल्ली-लन्दन उड़ान में कारगो में बैठकर लन्दन पहुंच गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;